ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *241
TO BE ANSWERED ON: 18.03.2021

REGULATION OF ONLINE CONTENT

***241 SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR:**

Will the Minister of Electronics & Information Technology be pleased to state :

(a) the steps taken by Government to regulate social media platforms for curbing fake news and misinformation; and

(b) the measures taken by Government to put restriction on the use of social media platforms in election campaigns and to remove unlawful content?

ANSWER

MINISTER FOR ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)

(a) and (b): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *241 FOR 18-03-2021 REGARDING REGULATION OF ONLINE CONTENT

……..

(a) and (b): The social media platforms, for the user generated content made available on their platforms, are intermediaries as defined in the Information Technology (IT) Act, 2000. Section 79 of the Act provides exemption from liability to intermediaries, provided they follow certain due diligence and are required to disable/remove unlawful content relatable to Article 19(2) of the Constitution, on being notified by appropriate government or its agency or through court order. In order to provide enhanced user safety as also accountability of social media platforms, Government has released the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 under the Act that specifies the due diligence to be followed by all the intermediaries including the social media intermediaries.

The issue is not about use of social media but its misuse/abuse. The Rules basically enjoin upon social media platforms to create an effective grievance redressal mechanism, where any stance of fake post/ fake news or a women being portrayed in undignified manner needs to be resolved within stipulated timeframe. The Rules, therefore are designed to empower the users of social media against its abuse and misuse.

Further, section 69A of the IT Act, 2000 empowers Government to block any information generated, transmitted, received, stored or hosted in any computer resource in the interest of sovereignty and integrity of India, defence of India, security of the State, friendly relations with foreign states or public order or for preventing incitement to the commission of any cognizable offence relating to above.

The Government welcomes criticism, dissent and also the rights of people to ask questions on social media. However, this needs to be acknowledged that the fundamental right of speech and expression under article 19(1) is also subject to reasonable restrictions under article 19(2) of the Constitution which can be imposed in the interest of security,

safety and sovereignty of India, public order, friendly relations with foreign countries etc. It is equally important that social media should not be abused or misused to defame, promote terrorism, rampant violence and compromise the dignity of women. It is for these challenges that the intermediaries are expected to remove/disable content as and when brought to the knowledge of intermediaries either through a court order or through a notice by appropriate government or its agency or when directed under section 69A of the IT Act 2000, following due process of law.

Also, Ministry of Information and Broadcasting has set up a dedicated cell (Counter Misinformation Unit) under Press Information Bureau (PIB) as a measure to counter fake news on policies, schemes, programs etc. by Government of India. The Unit has a presence on prominent social media platforms like Twitter, Facebook and lnstagram. The information is also available on https://pib.gov.in/factcheck.aspx. The unit takes suo moto cognizance of fake news going viral on social media and also on basis of outside complaints.

MeitY actively participated in a Committee specially constituted by Election Commission of India (ECI) to address the issue of misuse of digital and social media in election campaign. Based on the recommendations of the Committee, the ECI has worked closely with the industry. A code of

commitment was developed in last general election held in 2019. Both Election Commission and social media platforms worked as per the code of commitment for speedy removal of any objectionable or unlawful content. ECI has also set up a Social Media Communication Hub which is responsible for dissemination of information related to election, thereby minimising spread of misinformation including fake clips through different social media platforms.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *241

जिसका उत्तर 18 मार्च, 2021 को दिया जाना है।

27 फाल्गुन, 1942 (शक)

ऑनलाईन विषयवस्तु का विनियमन

***241. श्री जी.सी.चन्द्रशेखर**:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झूठी खबरों और गलत जानकारी को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को विनियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और उस पर से गैर-कानूनी विषयवस्तु को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) और **(ख)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

ऑनलाईन विषयवस्तु का विनियमन के संबंध में दिनांक 18.3.2021 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *241 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) और **(ख)** : सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में परिभाषित किए गए अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके प्लेटफार्म पर प्रयोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री के लिए माध्यस्थ हैं। अधिनियम की धारा 79 में माध्यस्थों को दायित्व से छूट प्रदान की गई है, बशर्ते कि वे कुछ बातों का यथोचित रूप से ध्यान रखें और सरकार या उसकी किसी उपयुक्त एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर या अदालत के आदेश के माध्यम से उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(2) से संबंधित गैरकानूनी सामग्री को निष्क्रिय करना/हटाना अपेक्षित है। संवर्धित प्रयोक्ता सुरक्षा प्रदान करने और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की जवाबदेही के उद्देश्य से सरकार ने अधिनियम के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (माध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 जारी किए हैं, जिनका अनुपालन सोशल मीडिया माध्यस्थों सहित सभी माध्यस्थों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

मुद्दा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का नहीं बल्कि इसके दुरुपयोग का है। नियम मूल रूप से एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर लागू होते हैं, जहां फर्जी पोस्ट/फर्जी समाचारों या किसी महिला को अशोभनीय तरीके से चित्रित किए जाने की किसी भी स्थिति का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, ये नियम सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं को इसके दुरुपयोग के खिलाफ सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

इसके अलावा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के तहत सरकार भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था के हित में अथवा उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिए भड़काने से रोकने के लिए किसी भी कम्प्यूटर स्रोत में सृजित, प्रसारित, भंडारित अथवा होस्ट की गई किसी भी सूचना को ब्लॉक करने में सक्षम है।

सरकार सोशल मीडिया पर सवाल पूछने के लिए आलोचना, असंतोष और लोगों के अधिकारों का स्वागत करती है। हालाँकि, यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि अनुच्छेद 19(1) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, जिसे भारत की सुरक्षा और संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित में लागू किया जा सकता है। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने, हिंसा को बढ़ावा देने और महिलाओं की गरिमा से समझौता करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए माध्यस्थों से अपेक्षा की जाती है कि वे किसी न्यायालय के आदेश के माध्यम से या सरकार या उसकी उपयुक्त एजेंसी द्वारा नोटिस के माध्यम से ध्यान में लाए जाने पर या कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69क के तहत निर्देशित किए जाने पर सामग्री को हटा देंगे/अक्षम कर देंगे।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों आदि पर नकली समाचारों का मुकाबला करने के उपाय के रूप में प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के तहत एक समर्पित सेल (काउंटर मिसिनफॉर्म यूनिट) की स्थापना की है। इस यूनिट की ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपस्थिति है। इसकी जानकारी https://pib.gov.in/factcheck.aspx पर भी उपलब्ध है। यह इकाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी खबरों का स्वत: संज्ञान लेती है और इसके साथ ही बाहरी शिकायतों के आधार पर भी संज्ञान लेती है।

एमईआईटीवाई ने चुनाव अभियान में डिजिटल और सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे का निवारण करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा विशेष रूप से गठित समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया। समिति की सिफारिशों के आधार पर ईसीआई ने उद्योग के साथ घनिष्ठता से काम किया है। 2019 में हुए पिछले आम चुनाव में प्रतिबद्धता की एक संहिता तैयार की गई। चुनाव आयोग और सोशल मीडिया दोनों प्लेटफार्मों ने किसी भी आपत्तिजनक या गैरकानूनी सामग्री को शीघ्र हटाने के लिए प्रतिबद्धता संहिता के अनुसार काम किया। ईसीआई ने एक सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की स्थापना भी की है जो चुनाव से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से नकली क्लिप सहित गलत सूचनाओं का प्रसार कम से कम हो पाएगा।

*****

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, Twitter was asked by the Government to block 1,178 accounts for allegedly spreading disinformation on the farmers' protest. The sedition charges were filed against climate activist, Disha Ravi, for editing a Twitter toolkit. This is not going to suppress the voice of the citizens. I would also like to know the reasons for ordering such a ban.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I would like to very briefly say why these new rules have been created and also respond to your query immediately. India is proud to have nearly 140 crore users of social media networks like Linkedin, WhatsApp, Twitter and Facebook. They are free to do business in India. They have empowered ordinary Indians; they ask questions, and the Government welcomes dissent. The issue is not of use of social media, the issue is of abuse and misuse of social media. The second point is that internet is a powerful invention of human mind, but it should not become the monopoly of a few. We have taken a position that any attempt to create imperialism of internet by a few companies is not acceptable. Now, coming to the specific question, this is something based upon law and order. The police has taken action. It is under judicial process. Based upon reason, this House has to consider this.: Should some people abuse social media internationally to defame India, to promote secessionalism, is a larger question to be considered.

SHRI G.C. CHANDRASHEKHAR: Sir, I would like to know whether the Government is working on setting up a system that will look into the speedy redressal of cases, involving harassment of women and minorities, through digital platform.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: I am very happy that the new guidelines specifically enjoin that if the dignity of a woman is being sought to be compromised, like, her nude photo, her morphed photo, etc. is being displayed, then, they have to remove it in 24 hours. Secondly, they need to have a grievance redressal officer, whereby a complaint can be filed and the grievance be redressed. Therefore, what we are doing by these guidelines is to empower the users of social media who suffer the misuse of it.

श्री शक्तिसिंह गोहिल : सर, सोशल मीडिया बहुत पावरफुल और इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। ज्यादातर जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है और गाली-गलौज की जाती है, वह फेक आंइडेंटिटी से की जाती है, फेक आइडेंटिटी से क्रिएट किए हुए प्लेटफॉर्म से की जाती है। मैं आपके ज़रिए मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही है, जिससे ऐसे फेक एकाउंट्स न खुलें, उन्हें permanently रोका जाए और सच्ची आइडेंटिटी का उपयोग हो? क्या

सरकार यह करना चाहती है कि सरकार के खिलाफ कुछ किया, तो राष्ट्रद्रोह हो गया, लेकिन दूसरे नेता के खिलाफ गाली-गलौज हुआ, तो कोई एक्शन नहीं लिया! क्या आपके पास इसे रोकने के लिए कोई उपाय हैं? **...(व्यवधान)...**

श्री उपसभापति : प्लीज़, प्लीज़।

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, हम सोशल मीडिया पर आलोचना का स्वागत करते हैं। हम लोगों की भी आलोचना होती है, प्रधान मंत्री की होती है, मंत्री की होती है, विरोधी दल की होती है। हम लोकतंत्र में आलोचना का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात माननीय सदस्य ने बहुत सही कही कि कुछ लोग ज्ञान तो देते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि वे कौन हैं? हमने इस नई गाइडलाइन में इस बात का प्रावधान किया है कि सोशल मीडिया कंपनीज़ अपने यूज़र्स से voluntary verification लेंगी। Voluntarily, कोई दवाब नहीं है, सरकार इसके बाहर है। आप देश को तो ज्ञान देते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं, आपके ज्ञान का स्वागत है, लेकिन आप अपने को verify तो कर दीजिए कि आप कौन हैं और यह काम हम कर रहे हैं!

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, there were many reports of foreign interference in elections of other countries, through manipulation of social media, amongst other things. So, my query to the hon. Minister is: Do they have any intelligence information or apprehension about interference of foreign countries in the forthcoming State elections in India?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I can only say that my Department works in close cooperation with the Election Commission. The Election Commission has set up a dedicated cell to weed out fake news, fake media designed to influence; and I can only convey to this House, Sir, that when the Cambridge Analytica issue arose, we took a very tough action and that company today has been banned. It stopped its operation, and a CBI investigation is going on. Therefore, for maintaining the purity of India's electoral process, my Government, along with the Election Commission, works in close coordination to ensure that there is no influence on election by fake news, etc.

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, according to the new guidelines, the time-line for 'take down' of illegal content is 'flat 36 hours'. My supplementary question is this: Is

the Government contemplating content-gradation, the severity of content, and then fixing the time-limit for its take down?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: The hon. Member is a very seasoned intellectual. The guideline is very clear that you have to remove that within 36 hours only if it relates to the unity and integrity of India, safety and security of India, public order and the most important, the dignity of the women, which we have added, Sir, because, of late, a lot of morphed pictures, compromising, etc., used to come there. And, Sir, I want to convey to this House that in 2018 -- the hon. Deputy Chairman may recall -- there was a long debate in this House on fake news and dignity of women. As a Minister, a commitment was taken from me that these will be strengthened, apart from court orders. Therefore, we have clearly classified the kind of posts which have to be 'down' immediately within 36 hours. But as far as content-gradation is concerned, we don't wish to interfere. That is a job of the users of social media as to what they wish to say and also the platform. But the guideline clearly enjoins that you need to ensure an effective grievance redressal mechanism.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 242.